विचार बिन्दु

दुर्भावना अपने विष का आधा भाग स्वयं पीती है। –सैनेका

सायबर अपराधियों के बढ़ते हौसलें, आमजन में शिकायत की जानकारी का अभाव

देश दुनिया में साइबर अपराध के बढ़ते आंकड़े जहां चिंतित करने वाले हैं वहीं यह और भी आश्चर्यजनक और चिंताजनक हालात है कि लाख अवेयरनेस प्रोग्राम व मीडिया में आये दिन साइबर ठगी के समाचारों की भरमार के बावजूद देश में केवल 18 फीसदी लोग ही ऐसे हैं जिन्हें साइबर अपराध होने पर उसकी शिकायत कहां और कैसे करनी है कि जानकारी है। यह तो सरकारी आंकड़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जनवरी-मार्च, 2025 में कराये गये ताजातरीन सर्वे से यह आंकड़ें प्राप्त हुए हैं। दूसरी और यूपीआई से भुगतान में खासा बढ़ोतरी हुई हैं। आज ठेले पर सब्जी बेचने वाले से लेकर दो-पांच रुपए का सामान विक्रेता भी आसानी से यूपीआई से भुगतान प्राप्त कर रहा है। 2022-23 में जहां केवल 38 फीसदी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते थे वह आज बढ़कर 50 प्रतिशत के लगभग हो गया है। वास्तविकता तो यह है कि आज ऑनलाइन पेमेंट करना लोगों की आदत में आ गया है। जेब में रुपया-पैसा रखना या कहीं जाते समय साथ पैसा ले जाना लोगों की आदत में अब लगभग नहीं ही रहा है। पर तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद है और पिछले तीन सालों में ही साइबर अपराध के आंकड़ें तीन गुणा बढ़ गए हैं। सरकार की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आज मोबाइल पर किसी का नंबर डायल करते ही पहले साइबर अपराध से सचेत रहने की कॉलर ट्यूयून सुनने को मिलती है और उसके बाद बात होती है।

मोबाईल पर नंबर मिलाते ही नहीं अपितु सोशियल मीडिया के प्लेटफार्म खासतौर से इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर आजकल साईबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन या ब्लेक मेलिंग से सतर्क रहने का संदेश सुनने को मिलता है। इतने के बावजूद ठगी के आंकड़ें चेताने वाले हैं। मजे की बात यह है कि साइबर ठगी के इन रुपों से सबसे अधिक शिकार पढ़े-लिखे और समझदार लोग ही हो रहे हैं। लाख समझाईस के बावजूद एक ओर ठगों के हौसले बुलंद है तो ठगी के शिकार होने वाले लोगों की संख्या और राशि में मल्टीपल बढ़ोतरी हो रही है। खास बात यह है कि ठगी के केन्द्र व ठगी के तरीके से वाकिफ होने के बावजूद यह होता जा रहा है। हांलाकि झारखण्ड के जमातड़ा से ठगों के तंत्र को तोड़ दिया गया पर देश में एक दो नहीं अपितु 74 जिलों में इस तरह की ठगी करने वालों के हॉटस्पॉट विकसित हो गए। झारखण्ड, राजस्थान, हरियाणा और बिहार के केन्द्र पहले पांच प्रमुख सेंटर विकसित हो गए।

ऐसा नहीं है कि साइबर अपराध केवल और केवल भारत में हो रहे हैं अपितु यह विश्वव्यापी समस्या होती जा रही है। दुनिया के देशों में देखा जाए तो साईबर ठगी के मामलों में रशिया पहले पायदान तो यूक्रेन दूसरे स्थान पर है। इनके बाद चीन, अमेरिका, नाइजेरिया और रोमानिया का नंबर आता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है साइबर ठगों सारी दुनिया में सहज पहुंच है। लोगों की गाढ़ी कमाई को हजम करने में इन्हें विशेषज्ञता हासिल है। लोगों की कमजोरी को यह समझते हैं और उसी कमजोरी के चलते पढ़े लिखे और हौशियार लोगों को भी आसानी से ठगी का शिकार बना लेते हैं। जाल ऐसा की यह समझते हुए कि ऐसा आसानी से होता नहीं है फिर भी चक्कर में फंस ही जाते हैं और ठगों के आगे सरेण्डर होकर लुट जाते हैं।

डिजिटल अरेस्ट में डॉक्टर, रिटायर्ड जज, प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी सहित संभ्रात वर्ग के लोगों को आसानी से जाल में फंसाकर ठगी हो रही हैं वह भी करोड़ों तक की ठगी के उदाहरण मिल रहे हैं। झूठे मामलों में परिजनों को फंसने से बचाने का झांसा देकर ठगी हो रही है। मजे की बात यह है कि इस स्तर तक डर या भयाक्रांत हो जाते हैं कि किसी अन्य या पुलिस से समस्या साझा करने की हिम्मत भी नहीं कर पाते और ठगी के बाद हाथ मलते रह जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामलें तो दिनोंदिन बढ़ते ही जा रहे हैं।

हमारे देश में साइबर ठग या तो किसी तरह का लालच देकर लिंक भेजकर ठगी करते हैं या फिर डरा-धमकाकर आसानी से ठगी का शिकार बना लेते हैं। सरकार प्रचार के सभी माध्यमों से बार-बार व लगातार आगाह कर रही है कि ठगों द्वारा डराने वाले तरीके वास्तविक नहीं है। बैंक कभी भी बैंक डिटेल या ओटीपी ऑनलाइन नहीं मांगते पर पता नहीं कैसे ठगों के जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई लुटा बैठते हैं। ओटीपी दे देते हैं तो लिंक खोलने के लिए लाख मना करने के बावजूद लिंक खोलकर लुट जाते हैं। पुलिस अधिकारी बन कर जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का रास्ता अपनाया जा रहा है उस संबंध में अवेयरनेस अभियान के बावजूद ठगी का शिकार होने वालों की संख्या या राशि में कमी नहीं हो रही है। डिजिटल अरेस्ट में डॉक्टर, रिटायर्ड जज, प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी सहित संभ्रात वर्ग के लोगों को आसानी से जाल में फंसाकर ठगी हो रही हैं वह भी करोड़ों तक की ठगी के उदाहरण मिल रहे हैं। झूठे मामलों में परिजनों को फंसने से बचाने का झांसा देकर ठगी हो रही है। मजे की बात यह है कि इस स्तर तक डर या भयाक्रांत हो जाते हैं कि किसी अन्य या पुलिस से समस्या साझा करने की हिम्मत भी नहीं कर पाते और ठगी के बाद हाथ मलते रह जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामलें तो दिनोंदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दरअसल इसमें पुलिस, सरकारी जांच एजेंसी या प्रवर्तन निदेशालय के नकली अधिकारी बन कर इस कदर डरा देते हैं कि कई दिनों तक लगातार ऑडियो या वीडियो कॉल करके ठगी का शिकार बना लेते हैं।

ऐसा नहीं है कि सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हो। सरकार व वित्तदायी संस्थाओं द्वारा मीडिया के माध्यम से सजग किया जा रहा है। इसके साथ ही झारखण्ड के बड़े केन्द्र जमातड़ा को लगभग समाप्त कर ही दिया है। पर देष में 74 हॉट स्पॉट विकसित हो गए हैं। इनमें हरियाणा का नूंह, राजस्थान का डीग, झारखण्ड का देवघर, राजस्थान का अलवर और बिहार का नालंदा पहले पांच हॉट स्पॉट हो गए हैं। मीडिया द्वारा भी समय समय पर स्ट्रिंग कर इस तरह के केन्द्रों को एक्सपोज किया है पर ठगी कम होने को ही नहीं है। दरअसल आम नागरिकों को भी सजग होना ही होगा। अनजान नंबरों पर बात ही ना करें। ज्योंही कोई डराये-धमकायें तो बहकावें में आने के स्थान पर पडताल करें। इस तरह के हालात सामने आये तो परेशान होने के स्थान पर परेशानी को साझा करें, पुलिस का सहयोग लेने में भी संकोच ना करें। देखा जाए तो सजगता इस समस्या का समाधान हो सकती है। सबसे ज्यादा जरुरी यह हो जाता है कि लाख सजगता के बावजूद भी यदि साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं तो उस स्थिति में बिना किसी घबराहट और संकोच के कहां ओर कैसे शिकायत की जा सकती है इसकी जानकारी देने के लिए सरकारी संस्थाओं के साथ ही गैरसरकारी संगठनों को भी आगे आना होगा नहीं तो साइबर अपराध का जिस तरह से दायरा दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है उस पर अंकुश नहीं लग सकेगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल शनिवार 14 जून, 2025

पंडित अनिल शर्मा

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 12:22 तक, ब्रह्म योग दिन 1:13 तक, विष्टि करण दिन 3:47 तक, चन्द्रमा आज प्रातः 5:38 से मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-वृष, चन्द्रमा-धनु, मंगल-सिंह, बुध-मिथुन, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सवार्थ सिद्धि योग रात्रि 12:22 से सूर्योदय तक है। भद्रा दिन 3:47 से तक रहेगी। आज गुरू अस्त पश्चिम में प्रातः 7:05 पर होगा। आज चतुरथी व्रत है। चन्द्रोदय जयपुर में रात्रि 10:10 पर होगा।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः शुभ 7:14 से 9:01 तक, चर 12:27 से 2:09 तक, लाभ अमृत 2:09 से 5:34 तक।

राहूकालः 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:36, सूर्यास्त 7:17

मेष
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

मकर
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

तुला
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

कुंभ
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

कर्क
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

वृश्चिक
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

मीन
आर्थिक/वित्तीय मामलों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

''वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान'' केवल अभियान नहीं, आज की जरूरत है

आशुतोष अवाना

राजस्थान रेत की चादर ओढ़े एक ऐसा प्रदेश, जहाँ हर कण में संस्कृति साँस लेती है, हर पत्थर इतिहास कहता है और हर बूँद जीवन रचती है। यहाँ की भूमि वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की प्रतीक है, इस गौरवशाली धरोहर के नीचे एक अनकहा संघर्ष वर्षों से पलता रहा है वह है जल बचाने और सहेजने का संघर्ष, अपने अस्तित्व को बचाए और बनाए रखने का संघर्ष जिसमें अब तक विजय मिलती रही है।

राजस्थान ने सदियों पहले ही समझ लिया था कि पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, जीवन की नींव है। राजस्थान में ऐसे अनेक महान शासक हुए हैं जिन्होंने झीलें, बावड़ियाँ, टांके, जोहड़, कुंड और नाड़ियाँ जैसे जल संरक्षण के पारंपरिक ढाँचो को विकसित किया है, फिर वह उदयपुर में सन् 1362 महाराणा लाखा द्वारा निर्मित पिछोला झील हो या राजसमंद में 1660 में महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित राजसमंद झील या फिर अजमेर में 1135 से 1160 के मध्य राजा अर्णोराज चौहान के द्वारा निर्मित आनासागर झील।

यह सब केवल निर्माण नहीं थे बल्कि जल दर्शन की जीवंत मिसालें थीं। इन जल स्त्रोतों ने अकाल और सूखे के समय मानव और पशुओं को नया जीवन दिया, निर्माण के समय हजारों-लाखों श्रमिकों, कारीगरों को रोजगार मिला, स्थापत्य और अन्य कलाओं को संरक्षण मिला। वर्तमान में जल संरक्षण और प्रबंधन केवल इन संसाधनों और संरचनाओं के निर्माण मात्र तक ही सीमित नहीं है, समय-समय पर इनकी साफ-सफाई, रखरखाव भी उतना ही आवश्यक है। आज यह कार्य मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया जा रहा है, जिस कारण उन्हें आमजन राजस्थान के भागीरथ के रूप में देख रहे हैं।

एक युगांतकारी पहल :-यह प्रदेश जहां क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, वही दूसरी ओर सबसे कम वर्षा पाने वाला राज्य भी है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 500 मिमी. से भी कम है। ऐसे में यहाँ जल की हर एक बूँद अमृत है। इसी अमृत को सहेजने के लिए 5 जून, 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। यह एक अभियान मात्र न होकर आज की अनिवार्यता-कल के जीवन का आधार, राज्य की जलनीति का पुनर्जागरण और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता का परिणाम भी है। जहाँ हर बूँद को बचाना, हर तालाब को फिर से भरना और हर पीढ़ी को जल की जिम्मेदारी सिखाना ही इस अभियान की आत्मा है। यह अभियान केवल बाँध, तालाब या जलाशयों के निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक विजन डॉक्यूमेंट है जो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने की बुनियाद रखता है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जल दृष्टि-मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण करते ही जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने जल संरक्षण को केवल पर्यावरणीय विषय न मानकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्राथमिकता बना दिया है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में-

1. पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनरुद्धार

2. जलगृहों की डीसिल्टिंग (गाद हटाना), मरम्मत और सौंदर्यीकरण

3. वाटर रिचार्ज ज़ोन, चेकडैम और रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना।

4. साफ-सफाई एवं रखरखाव से जल संरचनाओं की कार्यक्षमता बढ़ाना।

5. विद्यालयों ,पंचायतों और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से जनजागरूकता

अभियान संचालित करना जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

जनभागीदारी अभियान से जन आंदोलन की ओर -मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों ने जल संरक्षण अभियान को स्लोगन से आगे ले जाकर राज्य की जलनीति भले ही बना दिया हो किन्तु मुख्यमंत्री के यह प्रयास तब तक पूर्ण सफल नहीं होंगे, जब तक यह केवल सरकार का काम न रहकर जन आंदोलन बने क्योंकि जल संकट का समाधान योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से अधिक जन चेतना में छिपा है। इसके लिए इसमें समाज की भागीदारी बेहद आवश्यक है। राजस्थान पहले भी चुनौतियों से लड़कर विजेता बना है, आज फिर वक्त आ गया है कि हम अपनी जल परंपरा को फिर से जीवित करें। जिस राजस्थान ने सदैव रेत में जीवन उगाया है, अब हम सब राजस्थानियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि अब हम हर बूँद में भविष्य उगायें।

आशुतोष अवाना
सहायक जनसंपर्क अधिकारी
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान

मनोरंजन का व्यापक स्त्रोत बन चुका है ओटीटी प्लेटफॉर्म

बाल मुकुन्द ओझा

आजकल घर घर में ओटीटी की चर्चा खूब हो रही है। मनोरंजन की दुनिया में कुछ नए नए प्लेटफॉर्म्स सामने आएं हैं जिनमें एक प्रमुख नाम है ओटीटी प्लेटफॉर्म। हमारे देश में कुछ ही समय में देखते-देखते ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भारी लोकप्रियता अर्जित की है। डेटा और इंटरनेट सस्ता होने और उंगलियों पर उपलब्ध होने के कारण ओटीटी युवाओं के लिए मनोरंजन का एक व्यापक स्त्रोत बन चुका है। आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं है बल्कि डिजिटल युग की जरूरत भी बन चुके हैं। इसने न केवल हमारी देखने की आदतों को बदला है बल्कि नई और अनूठी कहानियों को प्रस्तुत करने के लिए एक स्वतंत्र मंच भी प्रदान किया है। ओटीटी मनोरंजन की दुनिया का एक नया ठिकाना बन चुका है, और हर दिन इसका बढ़ता सब्सक्राइबर बेस इस बात का प्रमाण है। इस प्लेटफॉर्म के किसी भी समय और कहीं भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं।

फिल्म और टीवी सीरियल हमेशा सिनेमा हॉल/थिएटर और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से देखे जाते रहे हैं। लेकिन आजकल उन्नत प्रौद्योगिकी ने ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं के माध्यम से फिल्म/मूवी/शो देखना अधिक सुविधाजनक बना दिया है। यह घर पर देखने की सुविधा ही नहीं, अपितु एक बड़ा आकर्षण है कि वे अपने मोबाइल पर जहां से शो देखना छोड़ती हैं, वहीं से देखना जारी रख सकती हैं। ओटीटी की फुल फॉर्म ओवर द टॉप होती है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो कुछ और प्लेटफॉर्म्स की मदद से मोबाइल पर ही वेब सीरीज, फिल्में, और सीरियल उपलब्ध करा देता है। भारत में भी बहुत तेजी से ओटीटी का क्रेज बढ़ रहा है। अब लोग सिनेमा हाल के स्थान पर घर बैठे ओटीटी प्लेटफार्म पर ही हर प्रकार की सीरीज को देखना पसंद कर रहे हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में देश में ओटीटी देखने वाले दर्शकों की संख्या 550 मिलियन तक पहुंच गई है। यह 2023 की तुलना में काफी ज्यादा है, जो इस डिजिटल क्रांति के तेजी से बढ़ने का संकेत देता है। इंटरनेट की रफ्तार बढ़ना, स्मार्टफोन का चलन बढ़ना और टेलीकॉम कंपनियों के बीच डेटा के दाम कम करने की होड़ इस बढ़ते हुए दर्शक वर्ग का कारण है। दरअसल कोरोना महामारी के दौर में डिजिटल वर्ल्ड में एक गजब की क्रांति हुई। इस दौरान लोग घरों में बंद थे। उन्हें मनोरंजन की तलाश थी। विशेषकर युवा वर्ग अपने मोबाइल पर कुछ न कुछ खोज रहे थे। और उन्हें घर बैठे यह सुविधा ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सुलभ करा दी। इससे शहर से गांव तक ओटीटी प्लेटफॉर्म का चलन बढ़ गया। मोबाइल पर ही लोगों को मनपसंद वेब सीरीज, फिल्में और शो मिलने लगे। अब उन्हें कहीं जानें की जरुरत नहीं थी। सिनेमा हाल में तीन-चार घंटे बिताने की भी कोई जरुरत नहीं थी। देखते-देखते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सबका चहेता बन गया और मनोरंजन के साथ मोज़ मस्ती तक लोगों की पहुंच आसान हो गई। अमेरिका से होते हुए भारत में सबसे पहली बार साल 2008 में ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी।

रिलायंस एंटरटेनमेंट ने देश का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म Bigflix लॉन्च किया था। दो साल बाद 2010 में अगुन्नन ने NEXGTV नाम से ओटीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए। इनमें वीडियो ऑन डिमांड के साथ टीवी देखने की भी सुविधा मिली। वर्तमान में भारत में कई तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज़्नी हॉटस्टार वूट, हुलु, सोनी लिव, जी फाइव और एमएक्स प्लेयर आदि अब सब जगह आसानी से उपलब्ध है।

ओटीटी सर्विस वर्तमान में बहुत पॉपुलर हो गई है। ओटीटी जैसे जैसे लोगों में लोकप्रिय हुआ वैसे वैसे अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी इसमें शामिल हो गई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस में अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्ती बढ़ाई गई है, ताकि बच्चों और युवाओं को अश्लील तथा अनुचित कंटेंट देखने से रोका जा सके। वेब सीरीज में दरअसल देश के मनोरंजन परिदृश्य में बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और इस क्रांति के केंद्र में ओवर-द-टॉप (ओटीटी) की उल्लेखनीय भूमिका है। ओटीटी ने देश में बड़ी हलचल मचा दी हैं। ओटीटी से सबसे ज्यादा हमारा युवा वर्ग आकर्षित हुआ है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स, ऑडियो स्ट्रीमिंग, ओटीटी डिवाइसेस, वोइसआईपी कॉल, एवं कम्युनिकेशन चैनल मैसेजिंग आदि के लिए किया जाता है। ओटीटी प्लेटफार्मों में नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, हुलु और यूट्यूब टीवी शामिल हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म आमतौर पर फिल्मों, टीवी श्रृंखला, वृत्तचित्रों, लाइव स्पोर्ट्स और समाचार सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं।

ओटीटी प्लेटफार्म का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अमेरिका की दो सबसे बड़ी कंपनिया नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम ने भारतीय भाषा में कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। भारत में अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, जी 5, हॉटस्टार प्रीमियम, अल्ट बालाजी जैसे कुछ सबसे प्रसिद्ध एप्लीकेशन है जिनकी मदद से हम वेबसीरिज का आनंद उठा सकते है।

वेब सीरीज के संवादों में गाली-गलौज से लेकर लिंगसूचक, जातिगत और व्यक्तिगत टिप्पणी का बोलबाला अधिक हो रहा है जो हमारे सामाजिक ताने बाने को क्षतिग्रस्त कर रहे है। एक सर्वे के अनुसार वेबसीरीज में समाहित सामग्रियों का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और दिल्ली के उत्तरदाताओं के मत को इकठ्ठा किया है। उत्तरदाताओं से मिले जवाब के अनुसार आज अमेज़न सबसे अधिक देखा जाने वाला ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है। वहीं आज ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर क्राइम पर आधारित शो या ऐसे शो जिसमें क्राइम सम्बन्धित कंटेंट अधिक शामिल हों, अधिक देखने को मिल रहे हैं। वहीं लगभग 70% लोगों का मानना है कि आज ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट लोगों, खासकर युवाओं के मन-मस्तिष्क, रहन-सहन और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश भारत है। आज हमारा युवा नशाखोरी के मकड़जाल में फंसता जा रहा है। इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म का खूब बोलबाला है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज में सरे आम नशे और अश्लीलता को परोसा जा रहा है। यह हम सब के लिए चिंता की बात है।

–बाल मुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

राजस्थान लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान में संस्था के अध्यक्षों की नियुक्ति कब?

अशोक कुमार

संस्थाओं का उद्धार कैसे होगा जब वर्षों से संसाधनों के प्रमुखों की नियुक्ति लम्बे समय से लंबित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) और माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान (आरबीएसई) में संस्था के अध्यक्षों की नियुक्ति क्यूँ नहीं हो रही है ? राजस्थान लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्तियों में देरी और रिक्तियों के पीछे के बहुआयामी कारणों का गंभीर विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि औपचारिक पात्रता मानदंड व्यापक होने के बावजूद, वास्तविक चुनौतियाँ मुख्य रूप से राजनीतिक विचारों, क्षमता और अखंडता वाले अधिकारियों की कथित कमी, और प्रणालीगत भ्रष्टाचार, विशेष रूप से पेपर लीक घोटालों, के महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय प्रभावों के जटिल अंतर्संबंध से उत्पन्न होती हैं। आर्थिक बाधाएँ इन अक्षमताओं का प्रत्यक्ष कारण होने के बजाय उनके परिणाम के रूप में अधिक दिखाई देती हैं। राजनीतिक प्रभाव और अनिर्णय, घोटालों के कारण संस्थागत विश्वसनीयता का क्षरण, और इसके बाद की कानूनी चुनौतियाँ प्रमुख कारक के रूप में सामने आती हैं। विशेष रूप से आरबीएसई के लिए अस्थायी या अतिरिक्त प्रभार नियुक्तियों पर निर्भरता, शासन में एक कमी को उजागर करती है। रिपोर्ट पारदर्शी, योग्यता-आधारित नियुक्तियों, संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करने और भ्रष्टाचार तथा मुकदमेबाजी का मुकाबला करने के लिए मजबूत तंत्रों की आवश्यकता पर जोर देती है, जिससे सार्वजनिक विश्वास बहाल हो सके और समय पर नेतृत्व सुनिश्चित हो सके।

आरपीएससी और आरबीएसई दोनों ही राजस्थान के शासन और शैक्षिक परिदृश्य में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जिसका प्राथमिक कार्य आवेदकों को योग्यता और आरक्षण नियमों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारी नौकरियों के लिए चुनना है । यह प्रतियोगी परीक्षाओं, स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार का आयोजन करता है। सार्वजनिक सेवा भर्ती में इसकी विश्वसनीयता सर्वोपरि है, जो हजारों उम्मीदवारों के करियर और राज्य प्रशासन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है। दूसरी ओर, आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके कार्यों में 12वीं बोर्ड परीक्षाओं और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं का संचालन शामिल है। आरबीएसई का प्रभावी कामकाज लाखों छात्रों और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव डालता है। उपयोगकर्ता की क्वेरी इस बात की पड़ताल करती है कि क्या गैर-नियुक्ति या देरी शिक्षकों की पात्रता की कमी, कुशल अधिकारियों की कमी, या आर्थिक/ राजनीतिक कारणों से है।

संस्थाओं का उद्धार कैसे होगा?

संस्थाओं के उद्धार हेतु ये कदम उठाए जा सकते हैं:-

रिक्त पदों पर त्वरित नियुक्तिः और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर तत्काल पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की जानी चाहिए।

भर्ती कैलेंडर का पालनः एक निश्चित भर्ती कैलेंडर तैयार किया जाए और उसका सख्ती से पालन किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता हो कि कब कौन सी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और कब पूरी होगी।

पारदर्शी और फुल-प्रूफ परीक्षा प्रणालीः पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए। बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी और जैमर जैसे तकनीकी उपायों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

कानूनी मामलों का त्वरित निपटाराः भर्ती से संबंधित कानूनी विवादों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जा सकता है या फास्ट-ट्रैक सुनवाई की व्यवस्था की जा सकती है।

नियमों की स्पष्टता और स्थिरताः भर्ती नियमों को स्पष्ट और स्थायी बनाया जाए ताकि बार-बार उनमें बदलाव की आवश्यकता न पड़े, जिससे कानूनी विवादों से बचा जा सके। पदोन्नति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करनाः विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित किया जाए और पदोन्नति प्रक्रियाओं में होने वाली देरी को कम किया जाए।

सरकार की प्रतिबद्धताः राज्य सरकार को इन नियुक्तियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भर्ती प्रक्रियाएं समय पर और निष्पक्ष तरीके से पूरी हों।

उत्तरदायित्व तय करनाः नियुक्तियों में देरी या अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय किया जाना चाहिए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो। अन्य राज्यों में, जहां नियुक्तियां नियमानुसार और समय पर होती हैं, वहां एक सुव्यवस्थित भर्ती प्रक्रिया, राजनीतिक इच्छाशक्ति, और कानूनी अड़चनों को कम करने के लिए प्रभावी तंत्र मौजूद होते हैं। राजस्थान को भी इन राज्यों से सीख लेकर अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार करने की आवश्यकता है।

–अशोक कुमार, पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर